आधी रात का लॉकडाउन

सेंटर फॉर अर्बन एंड रीजनल एक्सीलेंस (CURE) में, हम समावेशी विकास की पहल के नए-नए तरीकों की कल्पना करते हैं उनहे आजमाते हैं साथ ही समुदायों के साथ मिलकर अभिनव समाधानों को विकसित करते हैं.

CENTRE FOR URBAN AND REGIONAL EXCELLENCE

कोविड के दौर में गरीबों के लिए पानी और स्वच्छता

आधी रात को लॉकडाउन. सिंडरेला की तरह, 12 बजे सबकुछ सुलझ गया. हम सब भोजन, दवाइयां, सैनिटाइजर, साबुन, पैसा... और यहां तक की जरूरत से ज्यादा जमा करने की आपाधापी में उलझे थे लेकिन झुग्गी–झोपड़ियों में रहने वालों के पास यह विलासिता उपलब्ध नहीं है. दिल्ली के चाणक्य पुरी के विवेकानंद कैंप के रहने वाले सुख लाल के पास न कोई पैसा था, न जगह और न ही सब्जियों को स्टॉक करने के लिए फ्रिज. अगली सुबह पानी का टैंकर नहीं आया तो पीने का पानी भी नहीं था. अखबारों ने बताया कि टैंकर सेवा को स्थगित कर दिया गया था क्योंकि पानी के लिए टैंकरों पर टूट पड़ने वाले लोगों के बीच सामाजिक दूरी बनाए रखना कठिन था. कौन जाने कोरोनावायरस (कोविड –19) टैंकर की सतह पर कितनी देर कुंडली मारे बैठा रहता हो. अगले दिन, सामुदायिक शौचालय का मुलाजिम दिखाई नहीं दिया, या तो संक्रमित होने से बहुत डर गया होगा या पिर सड़कों पर बसें नहीं होने से पहुंच न सका हो. या ऐसा भी सकता है कि उसे टॉयलेट की सफाई के लिए डिटर्जेंट ही नहीं दिया गया हो. सुख लाल सोच रहा था कि वह खुद को बचाने के लिए हर कुछ घंटों में हाथ कैसे धोएगा, सामुदायिक शौचालय का उपयोग करने की प्रतीक्षा करते हुए कतार में अपने से आगे खड़े व्यक्ति से 6 फीट दूर कैसे खड़ा होगा. वह सोच में पड़ा था कि क्या उसकी मां को अगले महीने मासिक वेतन का भुगतान किया जाएगा. वह सोच रहा था कि क्या वह अगली सुबह अपना स्टाल लगा पाएगा. उसके पास सिर्फ 500 रुपये थे, क्या इतने पैसे से 21 दिन तक जीवन चल पाएगा? क्या उनके पास महीने के अंत में किराए का भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसा होगा? या दूसरों की तरह, उसे भी अपने गांव वापस चले जाना चाहिए?

हमने जब से शहरों में रहना शुरू किया है तभी से हमारे घरेलू नौकर, प्रेसवाले, ड्राइवर, सब्जी विक्रेता इन शहरों की झुग्गियों में रह रहे हैं लेकिन, मलिन बस्तियों में सेवाएं देने का हमारा दृष्टिकोण अपरिवर्तित रहा है. सामुदायिक शौचालय और सामुदायिक नल, पानी की आपूर्ति करने वाली पाइपलाइन और दूसरे बुनियादी ढांचे का अभाव है. कई लोग चालीस से अधिक वर्षों से इन झुग्गियों में रह रहे हैं, लेकिन चूंकि ये अनधिकृत बस्तियां सरकारी जमीनों पर बनी हैं इसलिए घरों में नल और शौचालय उपलब्ध कराने पर तो कभी विचार तक नहीं हुआ है. क्योंकि ऐसा करने का मतलब होगा कि उन्हें उस सार्वजनिक भूमि का स्वामित्व या उस भूमि पर स्थायी रूप से रहने की वैधता प्रदान करना जिसके 'बेहतर' उपयोग के लिए षहर के पास कोई दूसरी योजना हो सकती है. कोविड 19 जैसी महामारी ने हमें दिखाया है कि समावेशी होना और गरीबों के घरों में नल तथा शौचालय प्रदान करना कितना सार्थक होगा. यदि वायरस के संक्रमण तीसरे चरण तीन या सामुदायिक प्रसार के स्तर तक पहुंच जाता है तो भी हमें इसको लेकर कितना कम चिंता होना पड़ता.

भारत के दस शहरी घरों में से एक में उपलब्ध पीने का पानी खराब है (2011 की जनगणना). जिन लोगों को खराब पानी मिलता है, सबसे अधिक संभावना है वे शहरों की मलिन बस्तियों में रहने वाले गरीब ही होंगे. अनौपचारिक अनुमान कहते हैं कि देश में 7.5 करोड़ से अधिक अनौपचारिक प्रवासी श्रमिक हैं, अकेले निर्माण क्षेत्र में 5 करोड़ (जन साहस, 2020). कई, जैसा कि कोविड–19 ने साबित भी किया है, झुग्गियों में नहीं बल्कि छोटे ढाबों, कारखानों, प्रवासी हॉस्टलों में रहते हैं. पंजाब में उनके किराए के घरों को वेधा कहा जाता है जहां लोग काम करने की शिफ्ट के हिसाब से बिस्तर किराए पर लेते हैं. वहां दिया जाने वाला पानी साफ, पर्याप्त और उन्हें आसपास उपलब्ध है भी या नहीं, आज तक किसी ने कभी इसकी चिंता नहीं की. कभी किसी ने यह समझने की कोशिश नहीं कि 50 अन्य लोगों के साथ जिस शौचालय के वे साझा करते हैं उसे कभी साफ भी किया जाता है या नहीं और वह सीवर से जुड़ा हुआ है या फिर भूजल को दूषित कर रहा है. जब उन्होंने हैंड पंप से इस गंदे पानी को बाहर निकाला और पीने, खाना पकाने और हाथ धोने के लिए इस्तेमाल किया तो किसी ने उन्हें रोका नहीं. घर पर पानी नहीं मिलना सभी के लिए एक भयानक अनुभव है, और खासकर उन महिलाओं और लड़कियों के लिए जिनके ऊपर इसके संग्रह और भंडारण की जिम्मेदारी रहती है. यह उनके काम करने की सीमाओं को निर्धारित करता है. वे कब और कितनी देर तक वे स्कूल जा सकते हैं और बेहतर कमाई के लिए कौशल सीख सकते हैं इन सबकी सीमाएं तय करता है. खराब पानी उन्हें कमजोर करता है, उन्हें साधन, आवाज और चयन से वंचित करता है. ग्रीष्मकाल जल संकट को बदतर करता है, और वायरस के प्रसार को तोड़ने के लिए आवश्यक स्वच्छता बनाए रखने के लिए बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है.

समावेशी बुनियादी ढांचा, जो बराबरी वाला, गरिमापूर्ण और स्वस्थ हो, उसके लिए कुछ हटकर सोचने और करने की आवश्यकता होती है. इसके लिए पारंपरिक प्रथाओं में भी बदलाव की जरूरत है. सेंटर फॉर अर्बन एंड रीजनल एक्सीलेंस (क्योर) में, हम समावेशी विकास की कोशिश करते हैं और समुदायों के साथ मिलकर अभिनव समाधानों को विकसित करते हैं. ये बराबरी, स्थिरता और लचीलापन को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय रूप से डिजायन और विकसित किए गए हैं. समाधान सरल, सस्ते, वांछनीय और

उल्लेखनीय हैं. वे लोगों को जोड़ते हैं, स्वामित्व का भाव जगाते हैं और लगाव पैदा करते हैं और लोगों को अपने क्षेत्रों की प्राकृतिक पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए प्रेरित करते हैं. वे लोगों को संसाधनों का सृजनकर्ता बनाते हैं.

क्योर ने आगरा में गरीब समुदायों के साथ भागीदारी की है पानी की समस्या के समाधान और पारिस्थितिकी को पुनर्जीवित करने में उनके पारंपरिक ज्ञान का इस्तेमाल किया जा रहा है. गरीबों ने सात सामुदायिक वर्षा जल संचयन तालाबों और कई भूजल रिचार्जिंग सिस्टम की योजना बनाने, निर्माण, वित्तपोषण और रखरखाव में योगदान दिया है. पारंपरिक पुख्ता तकनीक के उपयोग से निर्मित, वे सात जलाशय प्रतिवर्ष स्कूलों, सामुदायिक हॉल, मंदिरों और मस्जिदों की छतों से 10 लाख लीटर वर्षा जल एकत्र करते हैं. जरूरत पड़ने पर लोग पीने और खाना बनाने के लिए इस पानी का इस्तेमाल करते हैं. वर्षा के पानी ने उन्हें पानी से परिपूर्ण तथा स्वस्थ और उनके खेतों को हरा–भरा बना दिया है. इसने स्कूलों में दाखिला और उपस्थिति (और शिक्षक प्रेरणा) को बढ़ाया है जिसका एक से अधिक पीढ़ी की गरीबी पर प्रभाव पड़ेगा. एक स्कूल में तीन सौ बच्चों को पीने के साफ पानी की आपूर्ति होती है. पानी की सफाई और आपूर्ति के लिए शहर के खर्चे में काफी बचत हो जाती है और इसके भूजल स्तर का पुनर्भरण करके उसे दुरुस्त किया जा रहा है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विशाल जल बैंक ने इन मोहल्लों की सामाजिक असमानता को दूर कर दिया है.

क्योर दिल्ली में रेजिलिएंट स्कूल विकसित कर रहा है. शौचालयों को ठीक करने और उन्हें क्रियाशील बनाने के साथ शुरुआत करके, क्योर ने इन स्कूलों की वर्षा जल संचयन संरचनाओं को पुनर्जीवित किया है. एक माइक्रो डिसेन्ट्रलाइज्ड वेस्टवाटर ट्रीटमेंट सिस्टम (लघु अपशिष्ट जलशोधन व्यवस्था) में हाथ धोने में इस्तेमाल हुए पानी को साफ किया जाता है, और उसे सब्जियों की बागवानी के लिए उपलब्ध कराया जाता है. भोजन और अन्य हरे कचरे से तैयार खाद का स्कूल के किचन गार्डन में उपयोग हो जाता है और इन क्यारियों से उगने वाली सब्जियां बच्चों के आहार में पोषण बढ़ा रही हैं.

सरलीकृत सीवर झुग्गी–झोपड़ियों में स्थानीयकृत किए गए हैं. ये संकरी–उथली सीवर लाइनें मलिन बस्तियों के जैविक अपशिष्ट को लेकर जाती हैं. जहां शहर के ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हैं वहां अपशिष्ट को इन सीवरों की मदद से बड़े सीवर तक पहुंचा दिया जाता हैं. जहां सीवरेज उपलब्ध नहीं है, वहां प्राथमिक सफाई के लिए अपशिष्ट को विकेन्द्रीकृत क्लस्टर सेप्टिक टैंक में ले जाया जाता है. सरलीकृत सीवर ने इन घरों को व्यक्तिगत शौचालय बनाने में सक्षम किया है– बिल्कुल वैसा ही जैसा कि हमारे आपके पास है. उन्होंने बहुत सस्ते में अपने शौचालय बनाए हैं और अपने छोटे घर में भी उनके लिए जगह निकाला है. मुख्य आपूर्ति पाइपों से पानी की पाइपलाइनों को झुग्गियों के अंदर लाया गया है, जिससे लोगों को घर पर पानी के नल मिल सकें. बायो–रेमेडियल–एरोबिक ट्रीटमेंट सिस्टम का उपयोग करके परनालों से होकर नदियों में पहुंचने

(CURE) (क्योर) रेजिलिएंट स्कूल्स को विकसित कर रहा है. शौचालयों को ठीक करने और उन्हें काम में आने लायक बनाने के साथ शुरुआत करके, (CURE) ने इन स्कूलों में वर्षा जल संचयन संरचनाओं को भी पुनर्जीवित किया है.

वाले काले गंदे पानी की सफाई की गई है. इन लोगों ने न केवल मलिन बस्तियों को स्वच्छ और स्वस्थ बनाया है, बल्कि पानी को फिर उपयोग के लिए तैयार किया है. स्वच्छ और स्वस्थ समुदायों ने आवासों को बेहतर करने लोगों के निवेश करने को प्रेरित किया है, सार्वजनिक स्थानों को फिर से सुधारा है और भूमि की कीमतों को ऊपर धकेल दिया है – जिससे गरीब, अमीर बन रहे हैं.

कोविड–19 के बाद, हम गरीबों के लिए बुनियादी ढांचे के बारे में सोचने के तरीके को या तो बदल सकते हैं, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो परिभाशित भौगोलिक क्षेत्रों में नहीं हो सकते, उन्हें शहर के तंत्र के साथ जोड़ा जा सकता है और बुनियादी सेवाओं तक समान पहुंच प्रदान की जा सकती है, या फिर सबकुछ अब भी वैसे ही चलने दिया जा सकता है जैसे चल रहा है. अगर हमें आगे बढ़ना है, तो शहर की सरकारों को चार प्रमुख चुनौतियों – स्थान, स्थानीयकरण, विरासत और भागीदारी– का समाधान करना होगा. भूमि पर स्वामित्व या स्थानीयता खराब पानी और स्वच्छता सेवाओं की कमी के मूल में है. मलिन बस्तियों के अवैध भूमि स्वामित्व के बावजूद, उन्हें घर पर नल और शौचालय से युक्त करने के लिए एक नीति होनी चाहिए. एक धारणा है कि झुग्गियां खराब भौगोलिक क्षेत्रों में बसी हैं, जहां सेवा प्रदान करना कठिन है, बहुत भीड़भाड़ है, वे जैविक और पर्यावरणीय दृश्टि से नाजुक भूमि पर बसी हैं. याद रखें, खराब भौगोलिक स्थिति को कुछ नवीन कल्पनाओं से प्रबंधित किया जा सकता है, और जैविक संदर्भों के अनुकूल बनाने के लिए पैमानों को छोटा करने तथा स्थानीयकरण के लिए थोड़ी सी डि–इंजीनयरिंग की जरूरत होगी. यह गरीबों को पारिस्थितिकी तंत्र का रक्षक बनाने का भी एक अवसर है. यह तभी हो सकता है जब लोग नियोजन की प्रक्रिया में शामिल होते हैं – निर्णय लेने की प्रक्रिया के लोकतंत्रीकरण और उनकी आवाज सुनने से उन समाधानों को खोजने में मदद मिल सकती है जो टिकाऊ होते हैं और जिसकी जिम्मेदारी समुदाय स्वयं ले और उपयोग करे. और अंत में, मलिन बस्तियों के लिए वही पुराने उपायों पर विचार और काम करने का सरकारी तरीका 1970 के दशक से नहीं बदला है. इस सोच की विरासत को विदाई दे देनी चाहिए और उनकी जगह बेहतर और न्यायसंगत सेवाओं की व्यवस्था होनी चाहिए. सरकारों को साहसी बनना ही होगा. पुराने ढर्रे को अलविदा कहते हुए नए परिप्रेक्ष्य से चिंतन आरंभ करना चाहिए. विकास का रास्ता समावेशी होना चाहिए. महामारी उस परिवर्तन के लिए रास्ता बना सकती है.

Dr Renu Khosla
Director, CURE India

लेखक के बारे में: डॉ रेणु खोसला CURE India की निदेशक हैं, और USAID के साथ दिल्ली और आगरा में "पानी और स्वच्छता में समझधारी" यानी PASS कार्यक्रम का नेतृत्व कर रही हैं. PASS का उद्देश्य गरीब समुदायों के बीच बेहतर और एकीकृत वाश सेवाएं प्रदान करना है-समानता और बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए घरों में नल और शौचालय, और स्थाई गरीबी उन्मूलन के लिए उत्पादकता बढ़ाना.